

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

खोजी खबरें-तेज नज़रें

प्रेरणा स्रोत - स्व. चुन्नीलाल सालवी

ये अखबार ही नहीं क्रांति का अभियान है। मानवता एवं लोकतंत्र का सजग प्रहरी, ये दुष्टों की मौत का सामान है।

वर्ष - 14 अंक - 22

12 जुलाई 2025, शनिवार

संपादक - दयाराम दिव्य

सहसंपादक - चाहत सालवी

मूल्य - 2 रु.

स्कूल बस और स्लीपर कोच में टक्कर,
10 साल के छात्र की मौत; कई घायल..!

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सुरज वर्मा

बिजयनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जिले के बाड़ी रोड पर स्थित संजीवनी स्कूल की बस और एक निजी स्लीपर कोच बस के बीच आमने-सामने की टक्कर में 10 वर्षीय छात्र मानवेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 अन्य स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है कैसे हुआ सड़क हादसा?

पुलिस के अनुसार स्कूल बस और स्लीपर कोच के बीच टक्कर सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुई। बताया कि स्कूल बस और स्लीपर कोच एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोट ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों वाहनों के चालकों की लापरवाही चलते यह हादसा हुआ है। इस स्कूल बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। सभी बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई। मृतक छात्र की हुई पहचान हादसे में मारे गए 10 वर्षीय मानवेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे छह दिन पहले ही संजीवनी स्कूल में दाखिल हुए थे। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र स्कूल बस के चालक के भतीजे थे और हादसे के समय बस की आगे वाली सीट पर बैठे थे। टक्कर के बाद उन्हें तुरंत स्थानीय राजकीय उपजिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन



गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस हादसे में 7 से 8 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां

उनका इलाज जारी है। स्कूल बस का चालक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है और वह बेहोशी की हालत में है। पुलिस ने वाहनों को जब्त किया हादसे की सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य

शुरू किया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाद-48 पर अक्सर तेज रफ्तार से वाहन चलाए जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है

माता-पिता तीर्थ गए, बेटे ने चुराए सोने चांदी के आभूषण

जोधपुर के माता का थान थाना पुलिस ने खुद के ही घर में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के माता पिता तीर्थ दर्शन के लिए गए पीछे से मौका पाकर अपने ही माता-पिता और दादी के गहने चुरा लिए और बाद में खुद ही पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दे आया, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अब आरोपी श्रवण गहलोत (27) पुत्र मगराज माली निवासी नवोड़ा बरा को गिरफ्तार किया है।

कपड़े की दुकान में हुआ घाटा दरअसल आरोपी ने कपड़े की दुकान खोली थी। जिसमें घाटा होने की वजह से उस पर 20 लख रुपए का कर्जा हो गया था। कई लोग उससे उधार पैसा भी मांगते थे और लोगों ने उसे उधार माल देना भी बंद कर दिया था। इसके चलते आरोपी ने एक योजना बनाई।

आरोपी के माता-पिता हरिद्वार में दर्शन करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। पीछे घर में आरोपी खुद ही अकेला था। इस पर उसने सोचा की माता-पिता घर से बाहर गए हुए



हैं और पीछे सोने चांदी के आभूषणों को चुरा लेता हूं और घर वालों को चोरी के बारे में सूचना दे दूंगा। इसी उद्देश्य के चलते आरोपी ने अपनी मां दादी और चाचा के उसके घर पर रखे सोने चांदी के आभूषणों को कमरे में रखे बक्से और तिजोरी से निकाल कर छुपा दिए। उसके बाद आरोपी ने घर के अंदर रखे बक्से, तिजोरी के ताले तोड़कर सामान को बिखेरकर नकबजनी का रूप दे दिया। बाद में अपने मकान के ऊपर बने कमरे में परिवार सहित जाकर सो गया।

सुबह होने पर आसपास के लोगों को बताया कि उसके घर पर अज्ञात चोर आए और चोरी कर सोने चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए और खुद ही पुलिस थाने पर जाकर सोने चांदी के चोरी होने की रिपोर्ट दे आया।

जयपुर में तेज-रफ्तार कार ने बच्चे समेत
तीन को कुचला:शराब के नशे मे था ड्राइवर

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

जयपुर में आज सुबह साढ़े 7 बजे कार ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया। घटना आमेर थाना इलाके में टंकी के पास की है। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया। जो शराब के नशे मे था। दुर्घटना थाने के एसएसआई माधोसिंह ने बताया- आज सुबह आमेर थाने से 2 किलोमीटर दूरी पर पानी की टंकी के पास एक कार ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है। बाइक सहित तीनों सड़क पर गिर गए। हादसे में हंडीपुरा रेगों का मोहल्ला निवासी लालीदेवी पत्नी

श्रवण लाल (37), जितेन्द्र (41) और लवीश (7) को गम्भीर चोट आई। तीनों घायलों को स्थानीय लोग 108 की सहायता से सीएचसी आमेर लेकर गए। लालीदेवी की रीड की हड्डी में गम्भीर चोट लगने से एसएमएस ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कार चालक शराब के नशे में होने कारण उसे आमेर थाना पुलिस ने शांतिभंग में गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी का मेडिकल कराया गया। कार को जब्त कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार आमेर थाना पुलिस को घटना की दी जानकारी दी। लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। लोग खुद घायलों को लेकर आमेर सीएचसी पहुंचे।

अवैध डोडा-चूरा तस्करी में शामिल 2

गिरफ्तार:भीलवाड़ा पुलिस ने जोधपुर से पकड़ा

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत रायला थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

रायला थाना प्रभारी बछराज ने बताया कि 14 मई को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, इस कार्रवाई के दौरान तस्कर नेशनल हाईवे 48 भीलवाड़ा रोड पर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। इस गाड़ी से 45 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया था और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

गाड़ी मालिक को भी गिरफ्तार किया

इस मामले में फरार गाड़ी मालिक दिनेश पिता जीवन राम गहलोत को



28 जून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इस मामले में शामिल दो आरोपियों की की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने दो को जोधपुर से पकड़ा पुलिस ने इस मामले में शामिल

विष्णु (26) पुत्र धर्म जाट निवासी जोधपुर और मनोज (21) पुत्र राम सिंह बिश्नोई निवासी जोधपुर की तलाश में जोधपुर पहुंची और जोधपुर पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार कर इन दोनों से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।

ये थे टीम में शामिल अवैध डोडा चूरा तस्करी के मामले में कार्रवाई करने गई टीम में रायला थाना प्रभारी बछराज, हेड कॉन्स्टेबल मुकेश कुमार, कॉन्स्टेबल घासी लाल, विक्रम,ओम प्रकाश और पुलिस थाना डंगियावास जोधपुर का विशेष सहयोग रहा।

सम्पादकीय

रिश्तों को संवारने की नई पाठशाला

देवानंद, मुमताज और चेतन आनंद अभिनीत एक हिट फिल्म आई थी-तेरे-मेरे सपने। इससे पहले देवानंद की ही फिल्म गाइड का गाना युवाओं की जुबान पर चढ़ गया था-तेरे-मेरे सपने अब एक रंग हैं। हालांकि पचास साल से अधिक के समय में बहुत कुछ बदल चुका है। संबंधों में भावुकता के मुकाबले 'प्रेक्टिकलिटी' ने स्थान बना लिया है। मामूली बातों पर संबंध खत्म हो रहे हैं। यदि किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं कहा तो भी 'टाटा-बाय बाय'। वैवाहिक संबंधों में स्थायित्व तक नहीं रहा। बच्चे भी अब



संबंध टूटने की राह में रोड़ा नहीं बनते। पिछले दिनों एक स्त्री ने चार बच्चों के होते हुए भी चार बच्चों के पिता से शादी रचा ली। इसी तरह एक महिला नौ बच्चों के होते हुए भी अपने पुरुष मित्र के साथ चली गई। उसका सबसे छोटा बच्चा आठ-नौ महीने का था। वह रो-रोकर मां को पुकारता रहा, लेकिन वह नहीं रुकी। यही हाल पुरुषों का भी है। किसी और महिला से संबंध बनाने के चक्कर में वे बाल-बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा संबंधों में हत्या भी जोर पकड़ रही है। कोई पत्नी को मार रहा है, कोई पति को, तो कोई लिव इन पार्टनर को। हाल में इसी अखबार में खबर छपी कि ऐसी घटनाओं से महिला आयोग बहुत चिंतित है। इसलिए दस राज्यों के 24 शहरों में ऐसे संवाद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां विवाह से पहले युवक-युवती आपस में बातचीत कर सकें। इन केंद्रों का नाम होगा-तेरे-मेरे सपने। यहां युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे विवाह में स्थायित्व आएगा। तलाक में कमी आएगी। घरेलू हिंसा भी रोकी जा सकेगी। महिला आयोग ने इन केंद्रों से जोड़े जाने वाले लोगों के लिए एक सिलेबस तैयार किया है। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। मूल रूप से यह बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सब पढ़ते हुए लगा कि क्या वाकई अब हमारे परिवारों में ऐसा कोई नहीं रहा, जो बच्चों को विवाह और उसकी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर सके। इसके लिए बाहर वालों की मदद चाहिए।

प्रधान संपादक - दयाराम दिव्य

ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार पत्थर फैक्ट्रीकर्मों की मौत



द मूवमेंट ऑफ इंडिया

थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे कामा चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर ड्राइवर ने टक्कर के बाद भागने की कोशिश की और पीछ कर रहे लोगों को भी कुचलने का प्रयास किया। हादसे के बाद, दोनों घायलों को तुरंत बिजौलिया के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भीलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में दिनेश ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक अविवाहित था।

थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे कामा चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर ड्राइवर ने टक्कर के बाद भागने की कोशिश की और पीछ कर रहे लोगों को भी कुचलने का प्रयास किया। हादसे के बाद, दोनों घायलों को तुरंत बिजौलिया के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भीलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में दिनेश ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक अविवाहित था।

भामाशाह राम कुंवार गोरा के द्वारा विद्यालय में वाटर कूलर भेंट राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

सुरज वर्मा

शाहपुरा शहर के तहनाल गेट में छात्र-छात्राओं के लिए बच्चखेड़ा निवासी श्री राम कुमार जी गोरा द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया इस अवसर पर भामाशाह गोरा ने अपने हाथों से विद्यालय के छात्र-छात्राओं को केले वितरण किये छात्रों द्वारा पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन अलग-अलग विद्यालयों में वर्षों से फलों का वितरण किया जाता है तथा पूरे वर्ष भर अमावस्या एवं



पूर्णिमा के अवसर पर भी अलग-अलग विद्यालयों में फलों का वितरण किया जाता है, आपने अनेक विद्यालयों में अपनी तरफ

से वाटर कूलर और शिक्षण सामग्री भेंट की है, श्री गोरा के कर कमलों से विद्यालय में पाम का पौधा लगाकर वृक्षारोपण का

शुभारंभ किया गया छ इस अवसर पर प्राचार्य सुमन कुमारी एवं विद्यालय परिवार के सदस्य सुनील सुखवाल, सूर्य प्रकाश शर्मा, महेश कुमार व्यास, हंसा हाडा, गुलाबचंद रेगर, शकुंतला मीणा, प्रतिभा सोलंकी, चंद्रकला टांक, अनीता व्यास, प्रेम मीणा एवं छात्राएं उपस्थित थे दृ विद्यालय परिवार द्वारा रामकुंवार गोरा एवम् उनके पुत्र भंवरलाल गोरा का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया और प्राचार्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने किया ट्रस्ट अध्यक्ष का सालवी का सम्मान

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

मात्रिकुंडिया बाबा राम देव मंदिर ट्रस्ट के नव निर्वाचित अध्यक्ष शंकर लाल सालवी तथा अन्य पदाधिकारीगण का भारतीय दलित साहित्य अकादमी चितोड़गढ़ के जिलाध्यक्ष मदन सालवी ओजस्वी द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक विषयों पर चिंतन मनन के साथ चर्चा की गई। इस दौरान ओजस्वी ने बताया कि आज अपनी युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवतावाद की ओर बढ़ाना और होगा। पढ़ने के साथ साथ जागरूकता भी बहुत आवश्यक



है। हमें अब अंधविश्वास आडम्बर रूढ़िवाद के कामों से मुक्त होना होगा।

कोचिंग सेंटर अब 'पोचिंग सेंटर' बन गए हैं- उपराष्ट्रपति

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भारत के उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ ने आज कहा, 'कोचिंग सेंटर अब 'पोचिंग सेंटर' बन चुके हैं। ये सुदृढ़ सांघों में प्रतिभा को जकड़ने वाले काले छिद्र बन गए हैं। कोचिंग सेंटर अनियंत्रित रूप से फैल रहे हैं, जो हमारे युवाओं के लिए, जो कि हमारे भविष्य हैं-एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। हमें इस चिंताजनक बुराई से निपटना ही होगा। हम अपनी शिक्षा को इस तरह कलकित और दूषित नहीं होने दे सकते। श्री धनखड़ ने आगे कहा, 'अब देश किसी सैन्य आक्रमण से नहीं, बल्कि विदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भरता से कमजोर और पराधीन होंगे। सेनाएं अब एल्लोरीद्ध में बदल गई हैं। संप्रभुता की रक्षा का संघर्ष अब तकनीकी स्तर पर लड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति ने तकनीकी नेतृत्व को नई राष्ट्रभक्ति का आधार बताते हुए कहा, 'हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं-एक नए राष्ट्रवाद के युग में। तकनीकी नेतृत्व अब देशभक्ति की नई सीमा रेखा है। हमें तकनीकी

नेतृत्व में वैश्विक अगुवा बनना होगा।'

श्री धनखड़ ने रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात-निर्भरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'यदि हम रक्षा के क्षेत्र में बाहर से तकनीकी उपकरण प्राप्त करते हैं, तो वह देश हमें ठहराव की स्थिति में ला सकता है। डिजिटल युग में बदलती वैश्विक शक्ति संरचनाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, '21वीं सदी का युद्धक्षेत्र अब भूमि या समुद्र नहीं है। पारंपरिक युद्ध अब अतीत की बात हो गई है। आज हमारी शक्ति और प्रभाव 'कोड, क्लाउड और साइबर' से तय होते हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), कोटा, राजस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री धनखड़ ने कहा, 'हम गुरुकुल की बात कैसे न करें? हमारे संविधान की 22 दृश्य-प्रतिमाओं में एक गुरुकुल की छवि भी है। हम सदैव ज्ञानदान में विश्वास रखते आए हैं। कोचिंग सेंटर को अपने ढांचे का उपयोग कौशल केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए करना चाहिए। मैं

नागरिक समाज और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि इस समस्या की गंभीरता को समझें और शिक्षा में पुनर्संयम लाने हेतु एकजुट हों। हमें कौशल आधारित कोचिंग की आवश्यकता है।' श्री धनखड़ ने अंकों की होड़ के दुष्परिणामों पर चेतावनी देते हुए कहा, 'पूर्णांक और मानकीकरण के प्रति जुनून ने जिज्ञासा को खत्म कर दिया है, जो कि मानव बुद्धिमत्ता का एक स्वाभाविक अंग है। सीटें सीमित हैं लेकिन कोचिंग सेंटर हर जगह फैले हुए हैं। वे वर्षों तक छात्रों के मन को एक ही ढर्रे में ढालते हैं, जिससे उनकी सोचने की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। इससे कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

छात्रों को अंकों से ऊपर सोचने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा, 'आपकी मार्कशीट और अंक आपको परिभाषित नहीं करेंगे। प्रतिस्पर्धी दुनिया में प्रवेश करते समय, आपका ज्ञान और सोचने की क्षमता ही आपको परिभाषित करेगी।' डिजिटल क्षेत्र की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, 'एक स्मार्ट ऐप जो ग्रामीण भारत में काम नहीं करता, वह पर्याप्त

स्मार्ट नहीं है। एक एआई मॉडल जो क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं समझता, वह अधूरा है। एक डिजिटल उपकरण जो दिव्यांगों को शामिल नहीं करता, वह अन्यायपूर्ण है। युवाओं से स्थानीय समाधान को वैश्विक स्तर तक ले जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'भारत के युवाओं को टेक्नोलॉजी की दुनिया के सजग संरक्षक बनना चाहिए। हमें भारत के लिए भारतीय प्रणालियां बनानी होंगी और उन्हें वैश्विक बनाना होगा।' डिजिटल आत्मनिर्भरता में भारत को अग्रणी बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'हमें अपनी डिजिटल नियति के निर्माता बनना होगा और अन्य देशों की नियति को भी प्रभावित करना होगा। हमारे कोड, डेटा वैज्ञानिक, ब्लॉकचेन इन्वेंटर और एआई इंजीनियर आज के राष्ट्र निर्माता हैं। भारत, जो कभी वैश्विक अग्रणी था, अब केवल उधार की तकनीक का उपयोगकर्ता बनकर नहीं रह सकता। पहले हमें तकनीक के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब यह समय सप्ताहों में सिमट गया है। हमें तकनीक का निर्यातक बनना चाहिए।

जड़ ही कमजोर है!



भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्रों को उनकी भावी जिंदगी के लिए तैयार कर रही है, या सिर्फ खानापुरी कर रही है? प्रकाश सर्वे से जो नजर आया है, वह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। हमारे बच्चों की जड़ ही कमजोर है। भारत में छठी कक्षा के 43 फीसदी छात्र जो पाठ्य (टेक्स्ट) पढ़ते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। इसी कक्षा के 54 फीसदी छात्र संख्याओं की तुलना करने या बड़ी संख्याओं को पढ़ने में अक्षम हैं। नौवीं कक्षा के 63 प्रतिशत छात्र संख्याओं के बुनियादी पैटर्न तथा भिन्न एवं पूर्णांक जैसे सांख्यात्मक समुच्चय को नहीं समझ पाते। ऐसे चिंताजनक तथ्य भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के -प्रकाश राष्ट्रीय सर्वेक्षण- से सामने आए हैं। इस सर्वेक्षण को नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस) के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह सरकार का अपना सर्वे है, किसी एनजीओ आदि का नहीं, जिस पर कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। यह सर्वे पिछले दिसंबर में हुआ। नतीजे अब जारी हुए हैं। सर्वेक्षण के दौरान तीसरी, छठी और नौवीं कक्षाओं के 21 लाख 15 हजार से अधिक छात्रों की पढ़ने-लिखने की क्षमता का जायजा लिया गया। ये छात्र 36 राज्यों में 781 जिलों के 74,229 स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यानी सर्वे से उपरी तस्वीर देशव्यापी है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या गणित के संदर्भ में सामने आई है। मगर अन्य विषयों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। मसलन, भूगोल का ज्ञान मापने के लिए नदियों और पहाड़ों की पहचान संबंधी सवाल पर 51 प्रतिशत छात्रों ने गलत जवाब दिए। इसी तरह पंचायतों का काम क्या है या त्योहारों का मौसम से क्या संबंध है, आदि जैसे प्रश्नों पर भी अधिकांश छात्रों का ज्ञान कमजोर पाया गया। तो बुनियादी सवाल यह उठता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्रों को उनकी भावी जिंदगी के लिए तैयार कर रही है, या सिर्फ खानापुरी कर रही है? आधुनिक दौर में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में महारत तथा सामाजिक- सांस्कृतिक चेतना के बिना अग्रणी राष्ट्र के निर्माण की बात सोची भी नहीं जा सकती। इन बिंदुओं पर बच्चों की जड़ ही कमजोर हो जाए, तो आगे लाख कोशिश कर भी उसकी पूरी भरपाई नहीं की जा सकती। तो प्रकाश से जो नजर आया है, वह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। मगर ये चिंता कौन करेगा, यह सवाल भी हमारे सामने खड़ा है।

महाराष्ट्र में क्या करेगी कांग्रेस!



महाराष्ट्र में कांग्रेस के सामने सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से सलाह मशविरा किए बगैर राज ठाकरे के साथ तालमेल कर लिया। दोनों भाई एक हो गए। मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों ने एक साथ रेली की और अब दोनों के कार्यकर्ता साथ साथ सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस के दूसरे सहयोगी शरद पवार को इससे कोई समस्या नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि वे इस तालमेल के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने ठाकरे बंधुओं की नजदीकी बनवाई है और इसका मकसद एकनाथ शिंदे को कमजोर करके भाजपा में उनकी स्थिति खराब करना है। अगर वे कमजोर हुए तो फिर ठाकरे बंधुओं की एकजुट पार्टी फिर भाजपा के साथ जा सकती है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति पुरानी नॉर्मल स्थिति में लौट सकती है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी की चिंता बड़ी है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे? बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हिंदी भाषी लोगों पर हमले के बाद कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। उधर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि गठबंधन रहेगा या नहीं। कांग्रेस के नेता अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के लिए राज ठाकरे के साथ जाना संभव नहीं है। भाषा और धर्म को लेकर उनकी राजनीति देश के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर सकती है। कांग्रेस की स्थिति अब माया मिली न राम वाली हो गई है। उद्धव ठाकरे के साथ जाकर उसने एक समझौता किया था और मुस्लिम मतदाताओं को भरोसा दिलाया था कि सब ठीक है। लेकिन अब उद्धव भी राज ठाकरे जैसी राजनीति करने लगे हैं तो कांग्रेस के सामने साक्षा का संकट भी खड़ा हो गया है। मुंबई में शरद पवार की पार्टी का ज्यादा असर नहीं है। सो, बीएमसी का चुनाव कांग्रेस को अकेले ही लड़ना होगा।

बिहार चुनावों में महिलाओं पर दांव के निहितार्थ!

बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य में राजनीतिक सरगमी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, नये-नये मुद्दों को उछाला जा रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड हो या तंत्र मंत्र के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों को जला देने की त्रासद घटना- नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर संदेह के सवालों के साथ मुखर विपक्षी दल इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के साथ ही कानून विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच, एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से दूरी बनाते हुए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत देकर सियासी परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं परिदृश्यों के बीच बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसला लेकर चुनावी सरगमियों को एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार सरकार का यह निर्णय केवल एक चुनावी रणनीति भर नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक परिवर्तन का संकेतक भी है। तय है कि इस बार के बिहार चुनाव के काफी दिलचस्प एवं हंगामेदार होंगे। सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के गहरे निहितार्थ हैं। एनडीए की नीतिश सरकार ने स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने एवं उनके लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के इस ब्रह्मास्त्र को दाग कर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में कर लिये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे “महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक समाधान” बताया, क्योंकि राज्य की महिलाएं कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से कहीं अधिक रही, 59.45 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया जबकि पुरुष केवल 53 प्रतिशत मतदान करने पहुंचे। यह आंकड़ा दिखाता है कि चुनावी जीत में महिला मतदाता कितनी निर्णायक हो सकते हैं, साफ है, सत्ता की चाबी वहां महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है और वे धार्मिक व जातिगत आह्राहों से अधिक लैंगिक हितों से प्रेरित हैं। बिहार उन शुरुआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबरदस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। चुनावों की दशा एवं दिशा बदलने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक किरदार निभाने के कारण ही हरेक राजनीतिक दल महिला वर्ग को आकर्षित करने में जुट गया है। राजद-कांग्रेस- वाम दलों का महागठबंधन ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का वायदा कर चुका है, तो राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के इस नीतिगत दांव को समझा जा सकता है। जातिगत और स्थानीय समीकरण धुनाने के लिए निश्चित ही यह एक संगठित चाल है, जहां जाति और आवासीयता दोनों को आधार बनाया गया। यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक खाई लगातार सिमट रही है। बिहार की बेटियां देश के अनेक महानगरों में अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर पहचान बना चुकी हैं। सूचना क्रांति, बढ़ती अपेक्षाओं और सामंती बंधनों के ढीले पड़ते जाने के कारण अब ग्रामीण बिहार की बेटियां भी ऊंचे सपने संजो रही हैं। हाल ही में बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यह देखा गया कि देश के विभिन्न प्रदेशों की योग्य लड़कियां इंटरव्यू देने आईं, जिनमें से अनेक ने सफलता प्राप्त की और अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कर रही हैं। निस्संदेह, यह एक सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील और समावेशी समाज का प्रतीक



है, जहाँ महिलाएं सीमाओं से परे जाकर अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें, तो महिला सुरक्षा, सामाजिक असमानता, आवास व पारिवारिक बाधाएं, और प्रवास की मजबूरियाँ अब भी मौजूद हैं। ऐसे में यदि सरकारें योग्य महिलाओं को उनके घर के आस-पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, तो यह न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम होगा, बल्कि सामाजिक संरचना में स्थिरता और पारिवारिक सहूलियत का भी कारण बनेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, पिक टॉयलेट, महिला पुलिस भर्ती में आरक्षण जैसे कई कदम इस सिलसिले में पहले ही उठाए जा चुके हैं। यह मान्यता कि बेटियाँ अब सिर्फ अपने घरों की शोभा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भागीदार हैं, नीति निर्माण में स्पष्ट झलकने लगा है। यह न केवल बिहार की महिलाओं को उनके अधिकार का अनुभव कराएगा, बल्कि बेरोजगारी से जूझते प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा के पलायन को भी रोकेंगा। इस फैसले से खास तौर पर निम्न और मध्यमवर्गीय महिलाओं को फायदा होगा, जिनके लिए दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करना एक बड़ा पारिवारिक और सामाजिक संकट बन जाता है। घर के पास नौकरी मिलने से न केवल सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थायी उपस्थिति और भूमिका भी मजबूत होगी। हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे नीतीश कुमार की चुनावी चाल बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं का वास्तविक समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही, बल्कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उछालकर वोट बंटोरने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि “महिला आरक्षण सही है, लेकिन रोजगार के अवसर कब हैं? सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया वर्षों से लटकी रहती है, परीक्षा की तारीखें टलती हैं, नियुक्ति पत्र देर से आते हैं, ऐसे में आरक्षण का लाभ कब और किसे मिलेगा?” उनकी बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आरक्षण की नीति। यह महिला आरक्षण अब केवल बिहार के स्थायी निवासियों अर्थात

डोमिसाइल महिलाओं के लिए ही होगा। यानी जो महिलाएं राज्य की स्थायी निवासी नहीं हैं, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा-उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा। इसलिये इसे केवल घरेलू हितों को साधने वाला प्रत्यक्ष प्रचार माना जा रहा है, जिसमें गैर-स्थायी निवासियों को अवसरों से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष इस कदम को डोमिसाइल नीति के अनुरूप बताते हुए सवाल उठा रहा है कि क्या इससे सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना नहीं बिगड़ जाएगी? बिहार में बेरोजगारी चुनावी चर्चा का मुख्य मुद्दा है। युवा खासकर उच्चशिक्षित वर्ग नौकरी की तलाश में है। 35 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ सरकार ने वेकेंसी क्रिएशन, युवा आयोग गठन, कृषि व सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जैसे उपाय किए हैं। 2025 के बिहार चुनाव बहुआयामी लड़ाई से परिपूर्ण है, जातिगत समीकरण, युवा और ग्रामीण विकास, मतदाता सूची संशोधन जैसे मुद्दों ने चुनावी माहौल को गहराई दी है। सरकार ने पिछले बजट में ‘महिला हाट’, ‘पिक बस’, ‘पिक टॉयलेट’, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजनाएं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए “संबल” वित्तीय सहायता जैसी महिलाओं को लुभाने वाली योजनाओं के प्रावधान किये हैं। नीतीश सरकार ने चुनावों को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। इस घोषणा के बाद पूरे बिहार में पेंशन के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार लाभार्थियों में हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है। यह कहना उचित होगा कि बिहार की राजनीति इस बार स्थानीयता, जातिगत समीकरण और सामाजिक कल्याण के मिश्रित आरोपणों के बीच गंभीर मुठभेड़ के दौर से गुजर रही है। चुनाव नतीजे ज्ञात करके कि क्या यह रणनीतियाँ सचमुच सतत परिवर्तन की ठोस बुनियाद रखेंगी, या चुनावी भाषण के बाद हवा में खो जाएँगी। नवीनतम ओपिनियन पोल बताते हैं कि एनडीए फिर सत्ता में लौट सकता है, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच मजबूत समर्थन के चलते। वहीं, महागठबंधन (आजैदी, कांग्रेस, अन्य) जातीय समीकरण (ईबीसी-ओबीसी) का आधार लेकर मुकाबले में है।

- तलित गर्ग

पुरानी गाड़ियों को चार महीने की राहत से क्या होगा!

राजधानी दिल्ली में उम्र की तय सीमा पूरी कर लेने वाली गाड़ियों को चार महीने की मोहलत मिली है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है? लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर उनकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी सही कंडीशन में है, ठीक से चल रही है और बेहतर रखरखाव की वजह से प्रदूषण भी नहीं फैला रही है तो उस के आधार पर उनको क्यों जन्त किया जा रहा है? यह सही तर्क है। व्यावसायिक गाड़ियां, जो 10 साल में पांच लाख या उससे भी ज्यादा किलोमीटर चली हों और बहुत प्रदूषण कर रही हैं उनको जन्त करना तो बनता है लेकिन निजी गाड़ी, जो 10 साल में एक लाख किलोमीटर भी नहीं चली हो उसे क्यों जन्त किया जा रहा है! इस आधार पर लोगों ने विरोध किया, खास कर मध्य वर्ग ने जो भाजपा का समर्थक



है तो दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्व्यूएम से इसे टालने का आग्रह किया। सीएक्व्यूएम ने

इस आग्रह को मंजूर करके इस अभियान को चार महीने टाल दिया है। अब सवाल है कि चार महीने में क्या बदल जाएगा?

चार महीने का समय है, अगर वे दिल्ली व एनसीआर से बाहर कहीं गाड़ी बेच सकते हैं तो बेच लें।

पक्षियों पर बढ़ता संकट!

बड़े पंखों वाले पक्षियों, बड़े शरीर वाले पक्षियों और सागर तटीय पक्षियों के अस्तित्व समाप्त होने का खतरा सामान्य पक्षियों की तुलना में अधिक है। वैश्विक स्तर पर पक्षियों की लगभग 5 प्रतिशत प्रजातियाँ समाप्त होने के कगार पर हैं पर सागर तटीय पक्षियों में से 12 प्रतिशत प्रजातियाँ खतरे में हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार पिछले 500 वर्षों के दौरान जितने पक्षी विलुप्त हो चुके, उससे लगभग तीन-गुने अधिक पक्षी अगले 50 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विलुप्तिकरण का प्रभाव केवल पक्षियों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा पारिस्थितिकीतंत्र इससे प्रभावित होगा। इस अध्ययन को ग्रेट ब्रिटेन के युनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वैज्ञानिकों ने किया है और इसे नेचर एण्ड ईकालजी इंवोल्यूशन नामक जर्नल में प्रकाशित किया है। इस अध्ययन के लिए पक्षियों की ज्ञात लगभग 10,000 प्रजातियों का, उनके आवासों का और उनके अस्तित्व पर खतरे का विस्तृत आकलन किया गया है। उनपर वर्तमान में और भविष्य में होने वाले खतरों का आकलन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के आधार पर किया गया है। रेड लिस्ट में उन सभी प्रजातियों की विस्तृत जानकारी है जो संकट में हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस अध्ययन के अनुसार अगले 100 वर्षों के भीतर पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियों का प्राकृतिक अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करना है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या के पोषण के नाम पर कृषि का क्षेत्र तेजी से बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों का काटा जा रहा है, घास के मैदानों को नष्ट किया जा रहा है और सागर तटीय भूमि पर भी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूमि उपयोग में परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने की दर अभूतपूर्व है। इसके अतिरिक्त शिकार, तापमान बृद्धि और जलवायु परिवर्तन, गैर-स्थानिक प्रजातियों को बढ़ावा देने से भी पक्षियों की प्रजातियों पर अस्तित्व के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पक्षियों के अस्तित्व पर संकट इस कदर गंभीर है कि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आज भी तापमान बृद्धि को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, तब भी

अगले 100 वर्षों में कम से कम 250 से 350 प्रजातियाँ विलुप्त हो जायेंगी। इतनी प्रजातियाँ पूरी तरह से समाप्त के राह पर हैं। पूरी तरह से समाप्ति की तरफ बढ़ती कुछ प्रजातियों को कैप्टिव प्रजनन विधि द्वारा बचाया जा सकता है। इस विधि में इनका प्रजनन प्रयोगशालाओं में या दूसरे सुरक्षित जगहों पर कराया जाता है और फिर प्राकृतिक आवासों में छोड़ा जाता है। वर्ष 1987 में उत्तरी अमेरिका में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजाति, कैलिफोर्निया कोडोर, प्राकृतिक आवास में पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। पर, इस प्रजाति के 22 सदस्य प्रयोगशालाओं या चिड़ियाघरों में मानव निगरानी में सुरक्षित रह गए थे। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को संरक्षित रखने का प्रयास कैप्टिव ब्रीडिंग की मदद से जारी रखा। यह प्रयास सफल रहा और अब तक 350 कोडोर को प्राकृतिक आवासों में छोड़ा जा चुका है। ऐसे सफल प्रयास यूनाइटेड किंगडम में भी किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार बड़े पंखों वाले पक्षियों, बड़े शरीर वाले पक्षियों और सागर तटीय पक्षियों के अस्तित्व समाप्त होने का खतरा सामान्य पक्षियों की तुलना में अधिक है। वैश्विक स्तर पर पक्षियों की लगभग 5 प्रतिशत प्रजातियाँ समाप्त होने के कगार पर हैं पर सागर तटीय पक्षियों में से 12 प्रतिशत प्रजातियाँ खतरे में हैं। बड़े शरीर वाले पक्षियों पर शिकार और जलवायु परिवर्तन का खतरा अधिक रहता है। बड़े पंखों वाले पक्षियों को आवास नष्ट होने के कारण खतरा बढ़ रहा है। तापमान बृद्धि के कारण पक्षियों के विलुप्तीकरण



के साथ ही उनके आकार बदलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक ठंडक के माहौल में पक्षी शरीर की गर्मी को अपने पंखों से बाहर नहीं जाने देते, पर चोंच और पैरों में रक्त वाहिकाओं का सघन जाल सहा है और इस कारण उससे शरीर की गर्मी

है कि तापमान बृद्धि से पक्षियों के केवल चोंच और पैर ही लम्बे और बड़े नहीं होंगे बल्कि उनके मुख्य शरीर का आकार भी छोटा होता जाएगा, जिससे उनपर गर्मी का असर कम हो सके। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट के अनुसार दुनिया में पक्षियों की कुल ज्ञात प्रजातियों में से 49 प्रतिशत प्रजातियों के सदस्यों की संख्या कम होती जा रही है, जबकि केवल 6 प्रतिशत प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनके सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तरी अमेरिका में 1970 के बाद से पक्षियों की संख्या लगभग दो-तिहाई रह गयी है। यूरोप में वर्ष 1980 से 2016 के बीच पक्षियों की कुल संख्या में एक-चौथाई की कमी आंकी गयी है। हमारे देश में पक्षियों की लगभग 1350 प्रजातियाँ हैं। लगभग 30000 पक्षी विशेषज्ञ और शीक्षिया पक्षियों पर अध्ययन करने वाले लोगों और संस्थानों के सम्मिलित अध्ययन को स्टेट ऑफ़ इंडियाज बर्ड्स नामक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। इसमें पक्षियों की 942 प्रजातियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 178 प्रजातियाँ संकट में हैं और उनपर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इन संकटग्रस्त प्रजातियों में नीलकंठ या इंडियन रोलर जैसी कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें कुछ समय पहले तक देश में बहुतायत में देखा जाता था, और आईयूसीएन भी उन्हें वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त नहीं मानता। नीलकंठ जैसी कुल 14 प्रजातियाँ हैं जिनके बारे में आईयूसीएन से तत्काल वैश्विक स्तर पर विस्तृत अध्ययन का उनके संरक्षण के स्तर में बदलाव करने का अनुरोध किया गया है। इतना तो स्पष्ट है कि दुनियाभर के पक्षियों की प्रजातियाँ संकट में हैं और बेतरतीब विकास, तापमान बृद्धि, जलों का काटना, शिकार, निर्जन द्वीपों पर आबादी का बसावा, शिकारी जंतुओं और पक्षियों का बढ़ता दावरा – इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पक्षियों के 50 प्रतिशत से अधिक प्रजातियों के सदस्यों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पक्षियों पर संकट गहराता जा रहा है, वैज्ञानिक इसे लगातार बात भी रहे हैं पर चरम पूंजीवादी सत्ता और अरबपतियों की बंधक बन चुकी दुनिया में तो अब सामान्य आदमी भी विलुप्त हो रहा है ऐसे में पक्षियों की बिसात ही क्या है?

